मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए बजट को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात

उत्तराखंड की सड़कों को 550 करोड़ दे केंद्र

देहरादून | विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में ग्रामीण सड़कों के लिए 550 करोड़ रुपये देने की मांग की। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज और पेयजल व स्वच्छता मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह ने इस पर सीएम को कार्यवाही का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में संपर्क मार्गों से वंचित आबादियों को सड़कों से जोड़ने के लिए नए प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी जाए। सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में योजना की सड़कों के पुनर्निर्माण को पहले मंजूर 60.61 करोड़ व अन्य कामों को पूर्व में मंजूर 1118.64 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पीएमजीएसवाई के लिए समर्पित प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट यूनिट (पीआईयू) गठित की हैं। वर्ष 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण को भारत सरकार ने 61.60 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

राज्य सरकार के अनुरोध पर यह सहमति बनी थी कि राज्य सरकार को यह राशि पीएमजीएसवाई के तहत सामान्य आवंटन के अलावा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि उत्तराखंड में 250 से अधिक जनसंख्या वाली 748 बस्तियों के लिए नई सड़क योजनाओं को मंजूरी दी जाए। फरवरी, 14 के बाद से अब तक कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ है। जबकि इनके लिए वन स्वीकृति, भूमि हस्तांतरण जैसी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज और पेयजल व स्वच्छता मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह से मुलाकात की। • हिन्दुस्तान

288 करोड़ मंजूर किए हैं केंद्र ने राज्य को पीएमजीएसवाई में

250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों के लिए नई योजनाएं मांगीं

अर्द्धकुंभ के लिए बजट को पीएम से लगाई गुहार

देहरादून | विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अर्द्धकुंभ कार्यों के लिए केंद्र सरकार से एकमुश्त 500 करोड़ रुपये की मांग की है। साथ ही पांच हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण अवधि दो वर्ष तक बढ़ाने की भी वकालत की। सीएम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे खत में ये बातें कही हैं।

उन्होंने कहा, अर्द्धकुंभ में 500 करोड़ में से 325 करोड़ के कार्य स्थाई प्रकृति के हैं। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 321 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी है, इसमें से अनेक कार्य पूरे होने वाले हैं। रावत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री व नीति आयोग से पूर्व में अर्द्धकुंभ के लिए 500 करोड़ का अनुरोध किया था, पर 166.67 करोड़ ही मंजूर हुए। यह राशि भी अब तक नहीं मिली है।

सीएम ने बताया, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्तराखंड को एनसीए में 1530, एससीए में 700 व एसपीए में 350 करोड़ का नुकसान हो रहा है। केंद्रीय करों में आर्थिक वृद्धि के बाद भी राज्य को अक्तूबर15 तक 1007 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उन्होंने इसकी भरपाई जल्द करने को कहा।

पंतनगर में हो एटीएफ की व्यवस्था : रावत

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर पंतनगर एअरपोर्ट में एविऐशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की व्यवस्था का आग्रह किया। सीएम ने कहा है कि पंतनगर बड़े इंडस्ट्रीयल हब के रूप में विकसित हो रहा है। एटीएफ की व्यवस्था न होने से पंतनगर से हवाई सेवाओं के संचालन में बाधा आ रही है। केवल एअर इंडिया ही हफ्ते में चार दिन पंतनगर से दिल्ली सेवा संचालन कर रहा है।